THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) The Jodhpur Mining Organisation (JMO) of fertilizer Corporation of India Ltd., which is located at Jodhpur is engaged in the mining of gypsum at Sri Mohangarh, Kawas and other areas in Rajasthan. Except for a marginal profit during 1991-92. Sri Mohangarh mines have incurred losses till 1995-96. The opeations in the Kawas mines have been profitable since 1990-91. The loss making mines located in Hanumangarh and Nagaur were surrender during the period from 1989 to 1994.

(b) The turnaround strategy of JMO is based on increasing its turnover and improving the operational efficiency.

**आई०डी०पी०एल० को हुए घाटे**

*2921. **श्री रामजी लाल**
**श्री अजीत जोगी:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) को गत कई वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ङ) क्या कम्पनी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि पिछले तीन महीनों से कर्मचारियों को वेतन और अन्य भुगतान नहीं किए जा रहे हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आई०डी०पी०एल० के **मजदूर संघों** ने कम्पनी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला):** (क) और (ख) जी हां। आई०डी०पी०एल० को 1993-94 में 70 करोड़ रु० का तथा 1994-95 में 77.52 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा हुआ है। 1995-96 में 108 करोड़ रु० का अनंतिम शुद्ध घाटा हुआ है। इस रुग्णता का मुख्य कारण है अपर्याप्त बिक्री प्रयास, अत्यधिक जनशक्ति तथा परवर्ती रोजगार की उच्च लागत, आवश्यक स्तर पर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करने में कम्पनी की असमर्थता, उच्च ब्याज का भार, उत्पाद-मिश्र (प्रोडक्ट मिक्स) में लचीलापन की कमी, अवरियात असुविधा इत्यादि हैं।

(ग) सरकार ने 1993-94 से 1995-96 तक कुल 148 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार 1.4.1993 से पूंजीगत पुनःसंरचना के लिए भी सहमत है जिसमें 150 करोड़ रु० के बकाया ऋण का इक्यूईटी में परिवर्तित करना, बाकी ऋण को 7 वर्ष में भुगतेय मोरटेरिम के साथ ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करना तथा 285 करोड़ तक के ब्याज/जुर्माना ब्याज को समाप्त / माफ करना शामिल है।

(घ) और (ङ) आई० डी० पी० एल० को 1996-97 में अत्यधिक वित्तीय असुविधा हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कम्पनी को 29.72 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आई० डी० पी० एल० प्लांट में उत्पादन अक्टूबर 1996 से बन्द है। जनवरी 1997 में कर्मचारियों को भुगतेय दिसम्बर 1996 तक का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर दिया गया है।

(च) कर्मचारियों की ओर से दो योजनाएं पेश की गयी हैं, जो वास्तव में रूपरेखाएं हैं। दोनों योजनाओं में आई० डी० पी० एल० के पक्ष में केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों/अन्य संगठनों तथा राज्य सरकारों से अनन्य खरीद वरीयता की बात कही गई है। वह अनन्य वरीयता खरीद अद्यतन नीति के अनुरूप नहीं है। इन योजनाओं में नई देयताओं तथा रोकड़ घाटे के निधियन इत्यादि के साथ अद्यतन देयताओं को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

**Ban on the Production, use and Import of Plastic**

2922. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that plastic bags, packaging materials etc. are eco-hostile, as reported in the "Hindustan Times" dated the 22nd February, 1996 and "Indian Express" dated the 9th December, 1996;

(b) whether their production has registered phenomenal increase;

(c) whether plastic trash is also being dumped in India;

(d) whether Government would consider banning the production, import and use of plastics since they constitute a threat to health and ecology;

(e) if so, by when; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILZIERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) Plastic bags, packaging materials etc. are not eco-hostile. On the contrary these are eco-friendly.

(b) The production of these materials have increased over the years. However, consumption of plastics is still below the world average.

(c) to (f) Government is conscious about potential hazards associated with import of plastic waste/scrap. Vide Public Notice No. 392(PN)/92—97 dated 1.1.97 issued by DGFT, only factory level waste/scrap (which is not put to any use whatsoever and as such can be termed as virgin or new material) will be allowed to be imported for further processing/use by domestic industries and it will be subjected to strict inspection. Other types of waste like municipal waste, post consumer discards etc. will not be allowed to imported. It will neither be possible nor desireable to ban the production and use of plastics as this wonderful materials is both supplementing the range of materials available to meet daily needs of common man at affordable prices with acceptable quality as also substituting natural materials like timber and metals thereby contributing to the preservation of ecology and environment. The increasing use of plastics in the medical services/ procession disproves the theory that plastics are a threat to health.

**Working Conditions of Forest Labourers in the country**

2923. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any existing machinery at the Central level to monitor the deployment of forest labourers in the country, their working conditions and related matters;

(b) whether any assessment has been made by Government in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

**Forest cover in the Country and World Bank sponsored afforestation schemes**

2924. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the percentage of forest cover, State-wise, of the country as on date;

(b) whether it is a fact that World Bank sponsored afforestation programmes are operational in the country;

(c) if so, the details of such programmes;

(d) whether Government propose to set up forest farmer cooperatives in the country to ensure that timber prices are determined by the farmers; and

(e) if so, by when a decison to that effect is likely to be taken?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Percentage of forest cover, State-wise of the country is given in Statement-I (*See* below)

(b) Yes, Sir.

(c) Details of World Bank sponsored afforestation programmes operational in